आन्ध्रप्रदेश राज्य व अन्य

बनाम

मैसर्स पायोनियर बिल्डर्स, ए.पी.

सितंबर 25, 2006

[एच. के. सेमा व डी. के. जैन, जे.जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908;

धारा 80 के तहत सूचना जारी न करना मुकदमें में कोई तत्काल और तत्काल राहत या तो मांगी गई या दी जा सकती थी, समय के शुरुआती बिन्दू पर रखरखाव पर कोई आपत्ति नहीं की गई और न ही लिखित बयान या अतिरिक्त लिखित बयान में ऐसी कोई याचिका दायर की गई। सी. पी. सी. की धारा 80 के तहत नोटिस जारी न करने के बारे में पूरी तरह से जानते हुए जल्द से जल्द समय पर ली गई स्थिरता और न ही लिखित बयान में उठाई गई ऐसी याचिका या मुकदमे में दायर अतिरिक्त लिखित बयान और मूल कार्यवाही में भाग लेने के बाद, यह मुकदमे की स्थिरता के रूप में एक नया मुद्दा उठाने के लिए खुला नहीं था क्योंकि यह माना जाएगा कि उसने आपत्ति को माफ कर दिया है।

प्रतिवादी की निविदा सबसे कम होने के कारण, उसे अधीक्षण अभियंता, श्री शैलम राइट शाखा नहर (संक्षेप में "एसआरबीसी") द्वारा रु. 8,42,93,617/- मूल्य

का काम प्रदान किया गया था। चूंकि आवंटित कार्य का केवल 50 प्रतिशत नियत तिथि तक पूरा किया जा सका, इसलिए प्रतिवादी ने निष्कासन की आशंका जताते हुए भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 8 और 20 के तहत एक याचिका दायर की, जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 26 और आदेश VII नियम 1 (सक्षेप में सी.पी.सी.) में मूल मुकदमे के रूप में पंजीकृत किया गया। प्रतिवादी को इस आधार पर अनुबंध से निष्कासित करने के लिए नोटिस जारी किया गया था कि वे अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति की दर को बनाए रखने में विफल रहे थे। प्रतिवादी ने अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसमें प्रतिवादीगण को अग्रिम संग्रहण और प्रदर्शन गारंटी के रूप में उनके द्वारा दी गई बैंक गारंटी को भुनाने से रोका गया। प्रतिवादीगण द्वारा मुकदमे का विरोध मुख्य रूप से गुण-दोष के आधार पर किया गया था, हालांकि यह कहा गया था कि "वादी का मुकदमा कानून या तथ्यों के आधार पर चलने योग्य नहीं है", इस पर आवेदन का कोई अलग जवाब नहीं दिया गया था। हालांकि, अधीनस्थ न्यायाधीश ने आवेदन को खारिज कर दिया था। व्यथित, प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में अपील को प्राथमिकता दी। जबकि अपील को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौते की भाषा और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिका में किसी भी निर्दिष्ट राशि के लिए कोई दावा नहीं था, प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया मुकदमा पोषणीय नहीं था। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि सलाह दी गई

तो वह प्रतिवादी को कानून के अनुसार संशोधन करने के लिए स्वतंत्र होगा। प्रतिवादी ने आदेश VI नियम 17 सी.पी.सी. के तहत लंबित मुकदमे में तीन आवेदन दायर किए, वाद पत्र में संशोधन के लिए, उत्पादन के लिए दस्तावेज का, प्रतिवादीगण द्वारा क्रमशः धारा 80 सी. पी. सी. के तहत नोटिस से राहत देने के लिए। वादपत्र में संशोधन की मांग करने वाले आवेदन में किए गए दावों के गुण-दोष के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा सभी आवेदनों का विरोध किया गया। आवेदनों के रखरखाव के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। हालांकि, तीसरे आवेदन के जवाब के अंतिम पैराग्राफ में, उन्होंने यह कहा कि चूंकि दावों की जांच करने के लिए समय की आवश्यकता थी, इसलिए "धारा 80 सी. पी. सी. के तहत नोटिस जारी करना आवश्यक था और अनावश्यक नहीं था।" अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा इन सभी तीनों आवेदनों की अनुमति दी गई। पारित आदेश इस प्रकार हैः "दोनों पक्षकार को सुना गया। मुझे मांगी गई राहत को अस्वीकार करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं मिलता है, जिसकी अनुमति दी गई।" उक्त आवेदनों में पारित आदेश को चुनौती नहीं दी गई। इसके अतिरिक्त दो अतिरिक्त लिखित बयान प्रतिवादीगण की ओर से दायर किए गए। दलीलों के आधार पर, लगभग अठारह मुद्दे तैयार किये गये। इनमें से कोई भी मुद्दा मुकदमे की रखरखाव से संबंधित नहीं था। मुकदमे के बाद, प्रतिवादी द्वारा किए गए कुछ दावों के संबंध में मुकदमा दायर करने की तारीख से ब्याज सहित फैसला सुनाय गया। हालांकि, प्रतिवादी द्वारा किए गए कुछ दावों को खारिज कर दिया गया था।

अपील और क्रॉस अपील दायर की गई। उच्च न्यायालय ने सभी अपीलों को खारिज कर दिया। इसलिए, वर्तमान अपील प्रस्तुत की।

अपीलार्थीगण द्वारा यह तर्क दिया गया कि धारा 80 सी. पी. सी. अनिवार्य और तत्काल आदेश के लिए किसी भी अनुरोध के अभाव में तथा तत्काल आदेश, विचारण न्यायालय द्वारा उस धारा के तहत नोटिस जारी करने की आवश्यकता को समाप्त करना उचित नहीं था। धारा 80 सी. पी. सी. की उप-धारा (2) के प्रावधानों को प्रस्तुत तथ्यों पर आकर्षित नहीं किया गया और इसलिए, धारा 80 की उप-धारा (1) के तहत अपेक्षित सूचना के अभाव में, विचारण न्यायालय मुकदमे पर विचार नहीं कर सका। यह भी तर्क दिया गया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 20 के तहत शुरू में प्रतिवादी द्वारा दायर याचिकाओं को आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. के तहत संशोधन आवेदनों के माध्यम से दीवानी मुकदमों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय दोनों मुद्दों पर कानून के स्थापित सिद्धांतों पर विचार करने में विफल रहा है।

प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया कि हालांकि शुरू में दायर किए गए मुकदमे को मध्यस्थता समझौते की अस्पष्ट भाषा के कारण मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 20 के तहत एक याचिका के रूप में रखा गया था, लेकिन वास्तव में यह एक दीवानी मुकदमा था। धारा 80 सी. पी. सी. के तहत वांछित नोटिस के लिए मुकदमे की पोषणीयता के संबंध में कोई आपत्ति लेने में विफल रहा है और आगे

विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने में विफल रहने, धारा 80(2) और आदेश VI नियम 17 सी.पी.सी. के तहत दायर आवेदनों को अनुमति देने और विचारण न्यायालय से पहले कार्यवाही में भाग लेने पर दोष यदि कोई हो तो माफ कर दिया गया और राज्य को अब इस तरह की आपत्तियां उठाने से रोक दिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया कि धारा 80 सी. पी. सी. केवल विशेषण कानून का एक हिस्सा है, केवल प्रक्रिया से निपटने के लिए, इसकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए ताकि इसे केवल तकनीकी आधार पर पराजित करने के बजाय न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए, यह आग्रह किया गया कि प्रतिवादी को धारा 80 सी. पी. सी. के तहत नोटिस के चरण में स्थानांतरित किया जाए, न्याय का उपहास होगा।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय अनुसार ने अभिनिर्धारित किया

1.1. केवल इस आदेश से छुट्टी देना कि "कोई मांगी गई राहत को अस्वीकार करने का कोई उचित आधार नहीं था" को स्वीकृति नहीं दी जा सकती।

1.2. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य ने इस आधार पर आवेदन की स्थिरता के बारे में कोई विशिष्ट आपत्ति नहीं उठाई थी कि किसी भी तत्काल राहत के लिए या तो प्रार्थना की गई थी या दी जा सकती थी और विशिष्ट तथ्यों और दोनों पक्षों के आचरण को ध्यान में रखते हुए, यह उचित नहीं है, जहाँ मामले को पुनः विचार के लिए अधीनस्थ न्यायाधीश को वापस भेजा जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा

धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत प्रतिवादी के आवेदन पर पारित आदेश उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं था। इसके अलावा मूल कार्यवाही में भाग लेने के बाद, जल्द से जल्द दोष को माफ करने और धारा 80 सी. पी. सी. के नोटिस जारी न करने के बारे में पूरी तरह से जानने के लिए राज्य के पास मुकदमे के रखरखाव के संबंध में नया मुद्दा उठाने का विकल्प नहीं था। धारा 80 सी.पी.सी. राज्य ने मुकदमें में दायर लिखित बयान या अतिरिक्त लिखित बयान में ऐसी कोई याचिका नहीं उठाई थी और इसलिए माना जाता है कि आपत्ति को माफ कर दिया गया है

[582-जी-एच; 583-ए-सी]

पी. ए. अहमद इब्राहिम बनाम भारतीय खाद्य निगम, [1999] 7 एस.सी.सी. 39; भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम राज किशोर सिंह, [2000] 9 एस. सी. सी. 174 और घनश्याम दास और अन्य बनाम भारत का अधिराज्य व अन्य, [1984] 3 एस. सी. सी. 446, संदर्भित।

भागचंद दग्डुसा गुजराती और अन्य बनाम भारत के राज्य सचिव, ए.आई.आर. (1927) पी. सी. 176; सवाई सिंघई निर्मल चंद बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. (1966) एस. सी. 1068 और बिहारी चौधरी और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, [1984] 2 एस. सी. सी. 627 का अवलोकन किया गया।

2.1. जबकि संशोधन में प्रार्थना की गई किसी भी दलील से मुकदमे की प्रकृति और चरित्र को बदलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और ऐसा नहीं हो सकता है कि अनुमति दी गई, आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय ने वाद के संशोधन के पहलू से निपटने के लिए पूरी तरह से छोड़ दिया और गुण-दोष के आधार पर दावों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़े। मामले के इस पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी निष्कर्ष के अभाव में वाद/याचिका में संशोधन की मांग करने वाले ठेकेदार के आवेदन पर अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की वैधता पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, खासकर जब, उच्च न्यायालय ने अपने पहले के आदेश में कहा था कि एक निर्दिष्ट राशि के लिए किसी दावे के अभाव में मूल रूप से प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं था। राज्य द्वारा दायर प्रथम अपीलों में उच्च न्यायालय को कुछ तथ्यात्मक पहलुओं पर भी विचार करना पड़ सकता है। आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन की रखरखाव और गुण-दोष के संबंध में मुद्दे पर विचार करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेज दिया गया। [1584-ई-एच; 585-ए-बी]

एल. जे. लीच एंड कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम मैसर्स जार्डिन स्किनर एंड कंपनी, ए.आई.आर.(1957) एस.सी. 357; श्रीमती गंगा बाई बनाम विजय कुमार और अन्य, [1974] 2 एस. सी. सी. 393 और बी. के. नारायण पिल्लई बनाम परमेस्वरन पिल्लई और अन्य, [2000] 1 एस.सी.सी. 712, संदर्भित।

सिविल अपीलीय न्याय निर्णयः सिविल अपील संख्या 6114/1999

उच्च न्यायालय, हैदराबाद आंध्रप्रदेश अपील सं. 2207/1996 में पारित निर्णय दिनांक 03.03.1999 से

के साथ

सी. ए. सं. 1005, 1006/2000 और 6115/1999

अनूप जी चौधरी, वी. आर. रेड्डी, एस. आर. अशोक, पी. विनय कुमार, डी. भारती रेड्डी, जी. एन. रेड्डी, सुनील मुरारका और वी. जी. प्रगसम पक्षकार की ओर से।

न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया-

डी. के. जैन, जे. ये चार क्रॉस अपीलें हैं, विशेष अनुमति द्वारा, दो निर्णयों और आदेशों के खिलाफ निर्देशित है, दोनों हैदराबाद में न्यायिक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.1999 को अपील संख्या 2206-2207/1996 और 236-237/1998 में दिये गये।आंध्र प्रदेश राज्य, मुकदमे में पहला प्रतिवादी और वादी, अर्थात् मैसर्स पायनियर बिल्डर्स, इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, हैदराबाद, जिसे इसके बाद "ठेकेदार" के रूप में संदर्भित किया गया है, हमारे सामने अपीलकर्ता है। चूँकि सभी अपीलों में शामिल तथ्यात्मक मैट्रिक्स और कानून के प्रश्न सामान्य हैं,

इसलिए इन निर्णयों द्वारा इनका निपटारा किया जा रहा है। हालाँकि, हम सिविल अपील संख्या 6115/1999 के तथ्यों का उल्लेख करेंगे।

2. वर्ष 1988 में किसी समय, अधीक्षण अभियंता, श्रीशैलम राइट ब्रांच कैनाल (संक्षेप में "एस. आर. बी. सी."), मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 2 ने योग्य स्रोत देशों के पूर्व-योग्य बोलीदाताओं से निविदाएं आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी किया, जिसमें एस. आर. बी. सी. की संरचनाओं की खुदाई, अस्तर और निर्माण के काम के लिए भारत भी शामिल था। यह एक समयबद्ध परियोजना थी, जो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से ऋण द्वारा समर्थित परियोजना थी।

3. ठेकेदार की निविदा न्यूनतम होने के कारण, उसे रु. 8,42,93,617/- का काम दिया गया। एक औपचारिक समझौता निष्पादित किया गया। काम पूरा करने का समय स्थल सौंपने की तारीख से छत्तीस महीने था। अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 57 में विवादों के समाधान की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। वह इस प्रकार हैः

"57. विवादों का समाधानः

(1) 50,000/-रुपये और उससे नीचे के दावों का मध्यस्थता द्वारा निपटान।

सभी विवाद या मतभेद जिनके संबंध में इंजीनियर या नियोक्ता का निर्णय, यदि कोई हो, अंतिम और बाध्यकारी नहीं हुआ है तो उपरोक्त विवाद में किसी भी पक्ष की पहल पर निम्नानुसार न्याय निर्णयन के लिए भेजा जाएगाः

(क) 10,000/-रुपये तक के दावे	अधीक्षण अभियंता एस.आर.बी .सी.सर्किल नंबर III नांदयाल, बंगनपल्ली
(ख) 10,000/-रुपये से उपर तथा 50,000/-रुपये तक के दावे	मुख्य अभियंता, प्रमुख सिंचाई, हैदराबाद

मध्यस्थता, भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

2. 50,000/-रुपये से ऊपर के दावों का निपटान

50,000/-रुपये से अधिक के सभी दावों का निपटारा सिविल सूट के माध्यम से सक्षम क्षेत्राधिकार न्यायालय द्वारा किया जाना है।"

4. ऐसा प्रतीत होता है कि नियत तिथि तक आवंटित कार्य का केवल 50 प्रतिशत ही पूरा किया जा सका है। निष्कासन की आशंका से दिनांक 24.03.1992 को ठेकेदार ने भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 8 और 20 के तहत एक याचिका दायर की, जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 26 और आदेश VII नियम 1 (संक्षेप में "सी. पी. सी.") के साथ पढ़ी गई, निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ एक मूल मुकदमे के रूप में पंजीकृत हैः

"(क) अनुबंध की धारा 2 के खंड 56 और 57 के तहत वादी और प्रतिवादी के बीच उत्पन्न होने वाले पैरा 17 में उल्लिखित विवादों की मध्यस्थान करें और प्रतिवादीगण को वादी को देय निर्धारित राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दें।

(ख) या वैकल्पिक रूप से प्रतिवादीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष समझौता दाखिल करने और मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत वादी और प्रतिवादीगण के बीच उत्पन्न होने वाले पैराग्राफ 17 में निर्दिष्ट उक्त विवादों के निपटारे के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करें।

(ग) कार्य निष्पादन की तारीख से लेकर कार्य पूरा होने तक वादी को देय राशि पर 21 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करें।

(घ) लागत।"

5. दिनांक 26.03.1992 को प्रतिवादी संख्या 2 ने ठेकेदार को इस आशय पर अनुबंध से निष्कासित करने के लिए नोटिस जारी किया कि वे अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति की दर को बनाए रखने में विफल रहे हैं। दिनांक 13.04.1992 को ठेकेदार ने प्रतिवादीगण को संग्रहित अग्रिम और प्रदर्शन गारंटी के रूप में उनके द्वारा दी गई राशि 1,26,00,000/- बैंक गारंटी को भुनाने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। प्रतिवादीगण द्वारा मुकदमे का विरोध मुख्य रूप से गुण-दोष के आधार पर किया गया, हालांकि इसे टाल दिया गया कि "वादी का मुकदमा न तो कानून की दृष्टि से और न ही तथ्यों की दृष्टि से चलने योग्य है।" ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदन का कोई अलग जवाब दाखिल नहीं किया गया है। हालांकि, आवेदन को अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित ठेकेदार ने उच्च न्यायालय में अपील की, जिसे आदेश दिनांक 13.11.1992 द्वारा खारिज कर दिया गया। अपील को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौते की भाषा और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिका में किसी भी निर्दिष्ट राशि के लिए कोई दावा नहीं किया गया था, ठेकेदार द्वारा दायर मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं था। हालाँकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि

ठेकेदार वादपत्र में संशोधन करने के लिए कानून के अनुसार स्वतंत्र रहेगा, इस प्रकार की सलाह दी गई।

6. उक्त आदेश के आलोक में, दिनांक 17.01.1993 को ठेकेदार ने लंबित मुकदमे में तीन आवेदन दायर किएः (i) आई.ए. सं. 1/1993 आदेश VI नियम 17 सी.पी.सी. के तहत शिकायत के संशोधन के लिए; (ii) आई.ए. संख्या 2/1993 प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए; (iii) आई.ए. संख्या 3/1993 सी. पी. सी. की धारा 80 के तहत सूचना देने के लिए। सभी आवेदनों का प्रतिवादीगण द्वारा वाद में संशोधन की मांग करने वाले आवेदन में किए गए दावों के गुण-दोष के आधार पर विरोध किया गया। आवेदनों के रखरखाव के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। हालाँकि, आई.ए. नं. 3/1993 के उत्तर के अंतिम पैराग्राफ में, यह कहा गया है कि चूंकि दावों की जांच करने के लिए समय की आवश्यकता थी, इसलिए धारा 80 सी. पी. सी. के तहत नोटिस जारी करना आवश्यक था और ना कि जरूरत से ज्यादा। अधीनस्थ न्यायाधीश ने डॉकेट आदेश दिनांकित 02.02.1993 के माध्यम से इन सभी तीन आवेदनों की अनुमति दी थी। आई. ए. सं. 3/1993 में पारित आदेश इस प्रकार हैः

> "दोनों के तर्क सुने गये। मुझे इंकार करने का कोई ठोस आधार नहीं मिला, राहत मांगी गई, अनुमति दी गई।"

7. उक्त आवेदनों में पारित आदेशों को चुनौती नहीं दी गई थी। इसके बजाय प्रतिवादीगण की ओर से दो अतिरिक्त लिखित बयान दायर किए गए। दलीलों के आधार पर अठारह मुद्दों को तैयार किया गया था। इनमें से कोई भी मुद्दा मुकदमे की स्थिरता से संबंधित नहीं था। परीक्षण के बाद ठेकेदार द्वारा किए गए कुछ दावों के संबंध में मुकदमा दायर करने की तारीख से ब्याज के साथ मुकदमा दायर किया गया था, हालांकि प्रतियोगिता द्वारा व्यापक रूप से किए गए कुछ दावों को अस्वीकार कर दिया गया।

8. व्यथित होने के कारण, दोनों पक्षों ने उच्च न्यायालय से पहली अपील को प्राथमिकता दी (सं. 2206-2207/1996 और 236-237/1998) आक्षेपित आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसलिए, वर्तमान अपील प्रस्तुत की।

9. राज्य की ओर से उपस्थित श्री अनूप जी चौधरी, विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना गया और श्री वी. आर. रेड्डी, विद्वान वरिष्ठ वकील अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश आई.ए. नं. 1 व 3/1993, (1) आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. के तहत दायर संशोधन आवेदन के रखरखाव और (ii) धारा 80 सी. पी. सी. के तहत नोटिस के अभाव के लिए मुकदमे के रखरखाव से उत्पन्न केवल दो कानूनी मुद्दों पर ठेकेदार की ओर उपस्थित।

10. श्री चौधरी ने दृढ़तापूर्वक कहा कि धारा 80 सी. पी. सी. अनिवार्य होने के कारण और मध्यस्थ आदेश के लिए किसी भी प्रार्थना की अनुपस्थिति के कारण और तत्काल आदेश के लिए विचारण न्यायालय को अनुभाग में नोटिस जारी करने की आवश्यकता को समाप्त करना उचित नहीं था। यह दावा किया गया कि धारा 80 सी. पी. सी. की उप-धारा (2) के प्रावधान दलील दिए गए तथ्यों पर आकर्षित नहीं थे और इसलिए, धारा 80 की उप-धारा (1) के तहत आवश्यक सूचना के अभाव में, विचारण न्यायालय मुकदमे पर विचार नहीं कर सका। विद्वान वकील ने यह भी आग्रह किया है कि ठेकेदार द्वारा शुरू में आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. के तहत संशोधन आवेदनों के माध्यम से मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 20 के तहत दीवानी मुकदमों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। समर्थन में पी. ए. अहमद इब्राहिम बनाम भारतीय खाद्य निगम और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड बनाम राज किशोर सिंह और अन्य, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 20 के तहत एक आवेदन को संशोधित करने की अनुमति देकर वसूली के लिए एक मुकदमे में परिवर्तित करना आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. के तहत यह कार्रवाई का एक बिल्कुल नया कारण पेश करने और कार्रवाई की प्रकृति को बदलने जैसा होगा। इस प्रकार यह दलील दी जाती है कि उच्च न्यायालय दोनों मुद्दों पर कानून के तय किए गए सिद्धांतों पर विचार करने में विफल रहा है।

11. इसके विपरीत, श्री रेड्डी ने तर्क दिया है कि यद्यपि शुरू में दायर मुकदमे को मध्यस्था समझौते की अस्पष्ट भाषा के कारण मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 20 के तहत एक याचिका के रूप में शैलीबद्ध किया गया था, लेकिन वास्तव में यह एक दीवानी मुकदमा था।विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि धारा 80 सी. पी. सी. के तहत नोटिस के अभाव में मुकदमे की स्थिरता के संबंध में कोई भी आपत्ति लेने में असफल रहे हैं और इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने में विफल रहने पर धारा 80 (2) और आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. के तहत दायर आवेदनों को अनुमति देने और विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में भाग लेने पर, दोष यदि कोई हो माफ कर दिया गया और राज्य को अब ऐसी आपत्तियां उठाने से रोक दिया गया है। घनश्याम दास और अन्य पर विचार पर विचार किया गया। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि धारा 80 सी. पी. सी. केवल विशेषण कानून का एक हिस्सा होने के नाते, केवल प्रक्रिया से संबंधित होने के कारण, इसकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए ताकि न्याय के कारण को कम किया जा सके और इसे केवल तकनीकता पर पराजित किया जा सके। वकील ने यह भी आग्रह किया है कि ठेकेदार को धारा 80 सी. पी. सी. के तहत नोटिस के चरण में भेजना न्याय का उपहास होगा।

12. निर्धारण के लिए जो पहला सवाल उठता है वह यह है कि क्या धारा 80 सी. पी. सी. के प्रावधानों का कथित रूप से अनुपालन न करने के कारण ठेकेदार द्वारा दायर मुकदमा विचारणीय नहीं था ?

धारा 80 सी. पी. सी. इस प्रकार से है:

"80. सूचना- (1) उप-धारा (2) में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, सरकार (जम्मू तथा कश्मीर राज्य की सरकार सहित) के विरुद्ध कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा या किसी लोक अधिकारी के खिलाफ उसकी आधिकारिक क्षमता में से ऐसे सार्वजनिक अधिकारी द्वारा किये जाने वाले किसी भी कथित कार्य के संबंध में, लिखित रूप से नोटिस दिए जाने या वहां छोड़े जाने के अगले दो महीने की समाप्ति तक के कार्यालय-

(क) केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमे के मामले में, [सिवाय इसके कि जहाँ यह रेलवे से संबंधित है], उस सरकार का एक सचिव;

(ख) केंद्र सरकार के खिलाफ किसी मुकदमे के मामले में जहां यह एक रेलवे से संबंधित है, उस रेलवे का महाप्रबंधक;

(ख ख) जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के खिलाफ मुकदमे के मामले में, उस सरकार के मुख्य सचिव या इस संबंध में उस सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी;

(ग) [किसी अन्य राज्य सरकार] के खिलाफ मुकदमे के मामले में, उस सरकार का सचिव या जिले का कलेक्टर;

***

***

और किसी लोक अधिकारी के मामले में, जो उसे कार्रवाई का कारण, वादी का नाम, विवरण और निवास स्थान और राहत का दावा करते हुए उसके कार्यालय में दिया गया या छोड़ दिया गया; और वाद में एक बयान शामिल होगा कि ऐसी सूचना इस तरह से दी गई है या छोड़ दी गई है।

(2) सरकार (जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार सहित) या किसी लोक अधिकारी द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में किए जाने वाले किसी भी कथित कार्य के संबंध में तत्काल या तत्काल राहत प्राप्त करने के लिए एक मुकदमा, अदालत की अनुमति के साथ, उप-धारा (1) द्वारा आवश्यक कोई नोटिस दिए बिना, शुरू किया जा सकता

है; लेकिन न्यायालय मुकदमे में राहत नहीं देगा, चाहे वह अंतरिम हो या अन्यथा, सिवाय इसके कि -

सरकारी या लोक अधिकारी, जैसा भी मामला हो, मुकदमे में मांगी गई राहत के संबंध में कारण दिखाने का एक उचित अवसरः

बशर्ते कि न्यायालय, यदि पक्षों को सुनने के बाद संतुष्ट हो, कि मामले में कोई तत्काल या तत्काल राहत देने की आवश्यकता नहीं है, उप-धारा (1) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के बाद वादपत्र को प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दें।

(3) ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में किए जाने वाले किसी कार्य के संबंध में सरकार के खिलाफ या किसी लोक अधिकारी के खिलाफ दायर कोई भी मुकदमा केवल उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सूचना में किसी त्रुटि या दोष के कारण खारिज नहीं किया जाएगा।

(क) वादी का नाम, विवरण और निवास इस प्रकार दिया गया था कि उपयुक्त प्राधिकारी या लोक अधिकारी नोटिस देने वाले व्यक्ति की पहचान कर सके और ऐसी सूचना उप-धारा (1) में निर्दिष्ट उपयुक्त प्राधिकारी के कार्यालय में दी गई थी या छोड़ दी गई थी और

(ख) कार्रवाई का कारण और वादी द्वारा दावा की गई राहत को पर्याप्त रूप से काफी दर्शाया गया था।"

13. धारा 80 की उप-धारा (1) को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि इसकी उप-धारा (2) में जो प्रावधान किये गये हैं, उसके अधीन सरकार या किसी लोक अधिकारी के खिलाफ कोई भी मुकदमा तब तक दायर नहीं किया जा सकता जब तक कि अपेक्षित नोटिस न दिया जाए। उक्त प्रावधान के तहत जैसा भी मामला हो ऐसे सरकारी या लोक अधिकारी को तामील किया गया है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि धारा 80 के संशोधन से पहले संशोधित धारा 80 के प्रावधानों में कोई निहितार्थ या अपवाद नहीं माना गया और वे स्पष्ट और अनिवार्य है। यह धारा न्यायालय पर एक वैधानिक और अयोग्य दायित्व लगाती है और धारा 80 के अनुपालन के अभाव में मुकदमा चलने योग्य नहीं है। (देखिएः भागचंद दग्डुसा गुजराती और अन्य बनाम भारत के राज्य सचिव; सवाई सिंघई निर्मल चंद बनाम भारत संघ और बिहारी चौधरी और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य) इस प्रकार, धारा 80 के तहत नोटिस की सेवा सरकार या लोक अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। इस धारा का विधायी उद्देश्य सरकार को मुकदमे की पर्याप्त सूचना देना है, जिसे उसके खिलाफ दायर करने का प्रस्ताव है ताकि वह निर्णय पर पुनर्विचार कर सके और खुद तय कर सके कि किए गए दावे को स्वीकार किया जा सकता है या

नहीं। जैसा कि बिहारी चौधरी (ऊपर) में देखा गया है, इस धारा का उद्देश्य न्याय की प्रगति और अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचकर सार्वजनिक भलाई सुनिश्चित करना है।

14. ऐसा लगता है कि इस प्रावधान ने वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किए क्योंकि यह एक सामान्य अनुभव का विषय है कि सरकार या संबंधित लोक अधिकारी द्वारा उक्त प्रावधानों द्वारा प्रदान किए गए अवसर का उपयोग करके शायद ही कोई मामला सुलझाया जाता है। अधिकांश मामलों में, धारा 80 के तहत दिया गया नोटिस अनुत्तरित रहता है। अपनी 14 वीं रिपोर्ट (27 वीं और 54 वीं रिपोर्ट में दोहराई गई) में, विधि आयोग ने कहा कि इस धारा के प्रावधानों ने बड़ी संख्या में मामलों में बड़ी कठिनाई पैदा की है, जहां सरकार या किसी लोक अधिकारी के खिलाफ निषेधाज्ञा के माध्यम से तत्काल राहत दी गई है। न्याय के हित में आवश्यक था, धारा को हटाने की सिफारिश की थी। तथापि, संसद की संयुक्त समिति, जिसे संशोधन विधेयक 1974 के तहत भेजा गया था, विधि आयोग से सहमत नहीं थी और आवश्यक संशोधनों/छूटों के साथ धारा 80 को बनाए रखने की सिफारिश की।

15. इस प्रकार, इसके अनुरूप, सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन अधिनियम, 1976) द्वारा मौजूदा धारा 80 को धारा 80 (1) के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया और उप-धारा (2) और (3) को दिनांक 01.02.1977 से प्रभावी किया गया। उप-धारा (2) ने अनिवार्य नियम के लिए एक अपवाद बनाया है कि सरकार या किसी

लोक अधिकारी के खिलाफ कोई भी मुकदमा तब तक दायर नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसे सरकारी या लोक अधिकारी को दो महीने का नोटिस नहीं दिया गया हो। प्रावधान उप-धारा (1) की कठोरता को कम करता है और न्यायालय को किसी व्यक्ति को उप-धारा (1) के तहत कोई नोटिस दिए बिना मुकदमा दायर करने की अनुमति देने का अधिकार देता है। यदि उसे यह पता चलता है कि मुकदमा सरकार या किसी लोक अधिकारी के खिलाफ तत्काल और तत्काल राहत प्राप्त करने के उद्देश्य से है। लेकिन, न्यायालय उप-धारा के तहत तब तक राहत नहीं दे सकता जब तक कि सरकार या लोक अधिकारी को राहत के संबंध में कारण बताने का उचित अवसर नहीं दिया जाता है। उक्त उप-धारा के प्रावधान में आदेश दिया गया है कि यदि न्यायालय की राय है कि कोई तत्काल और तत्काल राहत नहीं दी जानी चाहिए, तो वह उप-धारा (1) की आवश्यकताओं का पालन करने के बाद वादपत्र को प्रस्तुत करने के लिए उसे वापस कर देगा। उप-धारा (3), हालांकि वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक नहीं है, पर्याप्त अनुपालन का नियम लाने का प्रयास करती है और उप-धारा (1) की कठोरता में शिथिल करती है।

16. इस प्रकार, धारा 80 की उप-धाराओं (1) और (2) के संयुक्त पठन से विधायी आशय स्पष्ट है, अर्थात्, उप-धारा (1) के तहत नोटिस की सेवा अनिवार्य है, सिवाय इसके कि जहां न्यायालय द्वारा तत्काल और तत्काल राहत दी जानी है, जिस मामले में सरकार या किसी लोक अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता

है, लेकिन अदालत की अनुमति के साथ। न्यायालय की अनुमति एक पूर्ववर्ती शर्त है। इस तरह की छुट्टी बिना नोटिस दिए मुकदमे की स्थापना से पहले होनी चाहिए। हांलाकि धारा 80 (2) में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि छुट्टी अनुमति के लिए या अभी तक दिए गए आदेश को अनुरोध किए गए आधारों और उस पर मन के अनुप्रयोग को इंगित करना चाहिए। न्यायालय द्वारा शक्ति के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, अर्थात्, न्यायालय राहत प्रदान नहीं कर सकता है, चाहे वह अंतरिम हो या अन्यथा, सिवाय इसके कि सरकार या किसी लोक अधिकारी को मुकदमे में राहत के संबंध में कारण दिखाने का उचित अवसर दिया जाए।

17. ऊपर देखे गए विधायी आशय को ध्यान में रखते हुए, इस बात पर बहुत कम जोर देने की आवश्यकता है कि उप-धारा (2) के तहत न्यायालय में प्रदत्त शक्ति वास्तविक कठिनाई से बचने के लिए है और इसलिए मुकदमा दायर करने के लिए छुट्टी देने के कर्त्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। उसकी उपधारा (1) की आवश्यकतओं को अनुपालन किए बिना, केवल प्रार्थना की गई राहत की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, ना कि मामले के गुण-दोष को ध्यान में रखते हुए। इससे भी अधिक जब उप-धारा (1) के तहत नोटिस की कमी को भी पूरा किया जाता है तो इस प्रावधान के तहत तत्काल मामलों में भी सरकार या किसी लोक अधिकारी को कारण बताने का उचित अवसर दिए बिना इस प्रावधान के तहत राहत नहीं दी जाएगी। राहत के लिए प्रार्थना की गई। प्रावधान यह भी अनिवार्य करता है कि यदि न्यायालय की राय है कि

कोई तत्काल या तत्काल राहत देने योग्य नहीं है, तो उसे उप-धारा (1) में अनुध्यात आवश्यकताओं का पालन करने के बाद शिकायत को प्रस्तुत करने के लिए वापस करना चाहिए।

18. ऊपर उल्लिखित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हम उपलब्ध तथ्यों पर ध्यान देते हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधीनस्थ न्यायाधीश, दिनांक 02 फरवरी, 1993 के आदेश के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि "मांगी गई राहत को अस्वीकार करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं था।" यद्यपि राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चौधरी के निवेदन में कुछ सार हो सकता है कि नोटिस की आवश्यकता के वितरण की मांग करने वाले आवेदन को अनुमति देने वाला आदेश गुप्त है, लेकिन तथ्य यह है कि आवेदन को अनुमति देने से, प्रतिवादी राज्य को सुनने के बाद, न्यायाधीश ने राय दी है कि मुकदमा एक तत्काल और तत्काल आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से है। यदि ठेकेदार के खिलाफ संतुष्टि होती तो न्यायालय धारा 80 की उप-धारा (1) के संदर्भ में दोष को ठीक करने के बाद फिर से वाद पत्र को प्रस्तुत करने के लिए ठेकेदार शिकायत वापस करने के लिए बाध्य था। यद्यपि हम इस तरीके से सहमत नहीं है, जिसमें पूर्व में निकाला गया आदेश दिया गया है और अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदन के जवाब में, राज्य ने इसके बारे में कोई विशिष्ट आपत्ति नहीं उठाई। इस आधार पर आवेदन की स्थिरता कि किसी भी तत्काल और तत्काल राहत के लिए या

तो प्रार्थना नहीं की गई थी या दी जा सकती थी, जैसा कि अब हमारे सामने प्रचार किया गया है, हमारी राय है कि विशिष्ट तथ्यों और दोनों पक्षों के आचरण को ध्यान में रखते हुए यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहां मामला पुनः विचार के लिए अधीनस्थ न्यायाधीश को वापस भेजा जाना चाहिए। हमारे लिए यह मानना मुश्किल है कि धारा 80 (2) सी. पी. सी. के तहत ठेकेदार के आवेदन पर अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होकर सही नहीं है। तद्नुसार, हम मामले के इस पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं। उच्च न्यायालय ने माना है कि मूल कार्यवाही में भाग लेने के बाद, यह अब राज्य के लिए खुला नहीं है कि वह जल्द से जल्द दोष को माफ करने के मद्देनजर मुकदमे की स्थिरता के संबंध में एक नया मुद्दा उठा सके। उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि धारा 80 सी. पी. सी. के तहत नोटिस जारी न करने के बारे में पूरी तरह से जानते हुए भी राज्य ने मुकदमे में दायर लिखित बयान या अतिरिक्त लिखित बयान में ऐसी कोई याचिका नहीं उठाई गई थी और इसलिए माना जाता है कि उसने आपत्ति को माफ कर दिया है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि क्या वास्तव में छूट है या नहीं, यह सवाल प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है और यदि उठाया जाता है तो न्यायालय में उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यहाँ मामला नहीं है।

19. हम अब मामले के दूसरे पहलू पर विचार कर सकते हैं, अर्थात् क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिवचनों के संशोधनों को विनियमित करने वाले सिद्धांतों के अनुसार याचिका/वाद में संशोधन करने की अनुमति दी गई थी या नहीं?

20. दलीलों के संशोधन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए गए हैं। आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. अभिवचनों के संशोधन से संबंधित है और यह प्रावधान करता है कि न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी पक्ष को इस तरह से और ऐसी शर्तों पर अभिवचनों को बदलने या संशोधित करने की अनुमति दे सकता है जो न्यायसंगत हों और ऐसे सभी संशोधन किए जाएंगे जो आवश्यक हो सकते हैं। पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्नों को निर्धारित करने के उद्देश्य से आवश्यक होंगे। यह सामान्य बात है कि हालांकि किसी संशोधन को सभी परिस्थितियों में अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, फिर भी संशोधन की अनुमति देने की शक्ति व्यापक है और इसका प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है। यह भी सामान्य रूप से अच्छी तरह से तय है कि जब तक दूसरे पक्ष के साथ गंभीर अन्याय या अपूरणीय क्षति होने की संभावना नहीं है, न्यायालय को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ना कि अति-तकनीकी दृष्टिकोण, विशेष रूप से ऐसे मामले में जहां दूसरा पक्ष को लागत के साथ क्षतिपूर्ति की जा सकती है। दलीलों में उदारतापूर्वक संशोधन की अनुमति देने का प्रमुख उद्देश्य कार्यवाहियों की की बहुलता से बचना है (देखें: एल. जे. लीच एंड कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम मैसर्स जार्डिन

स्किनर एंड कंपनी, श्रीमती गंगा बाई बनाम विजय कुमार व अन्य और बी. के. नारायण पिल्लई बनाम परमेस्वरन पिल्लई और अन्य,) फिर भी एक कार्रवाई के विशिष्ट कारण को दूसरे के लिए प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है और न ही वाद के विषय को संशोधन के माध्यम से बदला जा सकता है। प्रिवी काउंसिल के निर्णय से निम्नलिखित अंश मा श्वे मिया बनाम मौंग मो हनानिंग, संक्षेप में उस सिद्धांत का सारांश देता है, जिसे अभिवचनों के संशोधन के लिए प्रार्थना पर विचार करते समय ध्यान में रखा जा सकता है।

न्यायालय के सभी नियम न्याय के उचित प्रशासन को सुरक्षित करने के प्रावधानों के अलावा और कुछ नहीं है और इसलिए यह आवश्यक है कि उन्हें उस उद्देश्य की पूर्ति करने और उसके अधीन होने के लिए बनाया जाए, ताकि संशोधन की पूर्ण शक्तियों का आनंद लिया जा सके और हमेशा उदारता से प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन फिर कार्रवाई के एक विशिष्ट कारण को दूसरे के लिए प्रतिस्थापित करने या संशोधन के माध्यम से वाद की विषय वस्तु को बदलने में सक्षम बनाने के लिए अभी तक कोई शक्ति नहीं दी गई है।

21. अभिवचनों में संशोधन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को संक्षेप में नोट करने के बाद, हम वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार कर सकते हैं।

22. संयोग से, संशोधन आवेदन की अनुमति देने वाले अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दायर नहीं किया गया है, बल्कि दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित

विद्वान् वकील ने ने हमारे सामने कहा है कि यह धारा 80 (2) सी. पी. सी. (1993 का आई.ए. सं. 3) के तहत आवेदन में पारित किए गए आदेश के समान था। उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य की ओर से और हमारे समक्ष यह तर्क दिया गया था चूंकि अनुरोध किए गए संशोधन का वाद की प्रकृति और चरित्र को बदलने का प्रभाव था, इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती थी। हालाँकि, हम पाते हैं कि हालाँकि प्रस्तुतिकरण को नोट किया गया है, लेकिन किसी तरह विवादित निर्णय में उच्च न्यायालय ने वाद के संशोधन के पहलू से निपटने के लिए पूरी तरह से चूक कर दी है और तुरंत गुण-दोष के आधार पर दावों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ा है। प्रारंभ में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 20 के तहत एक याचिका के रूप में आदेश VI नियम 17 सी. पी. सी. के तहत दायर करने के लिए एक आवेदन के माध्यम से इसे एक दीवानी मुक़दमे में परिवर्तित करने की मांग की गई थी। हमारे समक्ष यह अनुरोध किया गया है कि मूल याचिका भी, वास्तव में, एक दीवानी मुकदमे की प्रकृति में थी क्योंकि भुगतान की गई अदालत की फीस मध्यस्थता अधिनियम के तहत एक याचिका पर भुगतान करने की आवश्यकता से बहुत अधिक थी। हमारा विचार है कि मामले के इस पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी निष्कर्ष के अभाव में, हमारे लिए शिकायत/याचिका में संशोधन की मांग करने वाले ठेकेदार के आवेदन पर अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की वैधता पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। विशेष रूप से जब, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित

13.11.1992 आदेश में यह पाया गया था कि एक निर्दिष्ट राशि के लिए किसी भी दावे के अभाव में, मूल रूप से ठेकेदार द्वारा दायर किया गया मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं था। हमें लगता है कि उच्च न्यायालय को पहले मामले में कुछ तथ्यात्मक पहलुओं पर भी गौर करना पड़ सकता है, जिसमें अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा दिनांक 02.02.1993 को पारित (आई.ए. संख्या 1 और 3/1993 में) आदेश को चुनौती दी गई थी। इन परिस्थितियों में, हम आदेश VI नियम के तहत ठेकेदार द्वारा दायर आवेदन के गुण-दोष व योग्यता के संबंध में मुद्दे पर विचार करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेजना उचित समझते हैं।

23. परिणामस्वरूप, राज्य द्वारा दायर अपीलों को ऊपर बताई गई सीमा तक अनुमति दी जाती है। हालाँकि, हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हमने अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई डिक्री के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। हम इस मुद्दे को खुला रखते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त मुद्दे पर अपना निर्णय सुनाये जाने के बाद, पक्षकार के लिए वर्तमान अपीलों को फिर से शुरू करने सहित उचित कार्यवाही का सहारा लेना खुला रहेगा। हालाँकि, पक्षों को अपनी-अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

बी.के. अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नवीन मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।